school learning, non formal education and assistance to the disadvantaged alongwith physical amenities to be provided under the scheme of Environmental Improvement of Urban Slums (EIUS) through the formation of community groups. As per the reports available from the States/UTs, an expenditure of about Rs. 7.30 crores has been incurred on provision of such facilities under UBSP. The State Sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums seeks to provide basic physical amenities such as low cost water supply, drainage, sewerage community baths and latrines, paving and widening of streets and street lighting in identified slums. Since the beginning of the 7th Plan upto September 1991, about 125 lakh slum dwellers have been benefitted under the EIUS scheme.

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को आवासीय मकान

2666. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को आवासीय मकान का आवंटन नहीं किया जावेगा, यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह निर्णय किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगा यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को पूर्ण रूप से वारित करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, केवल दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों/कर्मचारियों जिन्हें कभी भी सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए पात्र कार्यालयों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, को अब विशेष रूप से दिसम्बर 1991 में वारित कर दिया गया है ।

छापेखाने

2667. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने छापेखाने हैं और उनमें "क" "ख" "ग" और "घ" श्रेणियों के कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1984 तक जो रिक्तियां हुई थीं उन्हें भर्ती पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न होने के बावजूद अब तक नहीं भरा गया है ; और

(ग) सरकार को इस के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस मंत्रालय के अधीन कलकत्ता में एक फार्म भण्डार और बाह्य मुद्रण शाखा के अलावा 20 मुद्रणालय हैं ।

1-3-91 की स्थिति के अनुसार इन सभी मुद्रणालयों/शाखाओं में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	कार्यरत व्यक्ति
"क"	42
"ख"	133
"ग"	10389
"घ"	2223

(ख) जनवरी, 1984 में जारी किए गए सरकार के आदेशों के अनुसार तथा परिणाम-स्वरूप जिन पदों के लिये भर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, के सिवाय आयोजना तथा आयोजना-भिन्न मौजूदा रिक्तियों तथा प्रचालन और गैर-प्रचलन पदों को भरा नहीं जाना था ।

1984 के पश्चात् की अवधि इस बात की पुष्टि करती है कि कुछ मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण और चार एककों को बन्द करने के निर्णय आदि का वर्तमान कर्मचारिवृंद पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि, चार एककों को बन्द करने के निर्णय के कारण सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध है, फिर भी अनिवार्य पदों को भरने की अनुमति दी गई है।

(ग) मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के कारण उत्पादन में वास्तव में वृद्धि हुई है। उत्पादन हानि के लिए मात्र विद्यमान रिक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बजट प्रावधान, कागज, पादर तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता भी इसके कारक हैं।

अम्बेडकर आवास योजना

2668. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मकानों के लिए अम्बेडकर आवास योजना के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस योजना के अधीन विभिन्न श्रेणियों के मकानों का आवंटन कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है और इससे श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को लाभ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) मकानों के आवंटन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लिए 10,000 व्यक्ति और जनता वर्ग के फ्लैटों के लिए 3000 व्यक्ति पहले ही पंजीकृत हैं। मध्यम आय वर्ग के फलैटों के लिए 7000 व्यक्तियों को अभी पंजीकृत किया जाना है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/पंजीकृत किए जाने वाले सभी 20,000 व्यक्तियों को 1994–95 तक फ्लैट आवंटित किए जाने की आशा है।

Sulabh Sauchalayas

2669. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Sulabh Sauchalayas have provided an alternative to scavenging in the country;

(b) if so, whether Government have any proposal to provide the facility throughout the country;

(c) if so, what are the details of plans in this regard;

(d) whether Government have decided to provide the facility in various parts of Madhya Pradesh; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since sanitation is a State subject, it is the responsibility of the State Governments and urban local bodies to provide proper sanitation facilities. The Government of India has since launched the scheme of low cost sanitation and liberation of scavengers for the eradication of manual scavenging in the country. The scheme envisages conversion of dry laterines/construction of new water seal pour flush laterines on 'whole town' basis. It is being operated through the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) by providing a mix of subsidy from the Central Government and loans from HUDCO in a synchronised manner to the State Governments for implementation of the programme.

(d) and (e) Proposals in respect of 57 towns in Madhya Pradesh have been approved for implementation under the above scheme.